

an>

Title: Discussion regarding need to expedite process of bringing back black money stashed abroad raised by Shri Mallikarjun Kharge on the 26<sup>th</sup> November, 2014 (Discussion concluded).

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up discussion under Rule 193 regarding need to expedite process of bringing black money stashed abroad.

Shri Mulayam Singh Yadav.

**श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) :** उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है। पिछले चुनाव में प्रधान मंत्री जी ने पूरे देश में घूम-घूमकर चुनाव प्रचार के दौरान काला धन वापस लाने का नारा दिया था। जनता ने आप पर आंख मूंद कर भरोसा किया। ... (व्यवधान) आपके प्रचार के दौरान देश की जनता ने विश्वास किया। उसी का परिणाम है कि आपकी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। आपने काला धन वापस लाने का जो नारा दिया था, जनता ने आप पर भरोसा किया और आपको सत्ता भी सौंप दी।

**15.16 ½ hrs (Shri Hukmdeo NarayanYadav in the Chair)**

सभापति महोदय, सरकार बनने के बाद आज तक सरकार ने, मोदी जी ने इसमें कोई भी प्रभावी कार्य नहीं किया गया, न सरकार ने अभी तक कोई विचार किया है, न अभी सदन को या देश को कुछ बताया है, जो आपने चुनाव के वक्त कहा था। कांग्रेस सरकार ने स्विज़रलैंड से एक समझौता किया था। काले धन की जानकारी प्रदान करने के लिए उस समझौते पर छह महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब तक ज्यादा से ज्यादा काला धन बैंको से निकाल लिया गया। अभी भी आपकी सरकार ने बयान दिए, प्रधान मंत्री जी ने बयान दे दिए और सरकार की तरफ से बयान दिए गए। इस बीच में काफी रूपया बड़ी तादात में बैंको से निकाल लिया गया। वया इस सरकार ने जानने की कोशिश की है कि यह जो रूपया निकाला गया, वह कहां गया? इस धन को निकालने वाले कौन-कौन थे? संसदीय कार्य मंत्री जी वया आपके पास सूती है? वया आपके पास जानकारी है? वह जानकारी सदन को जरूर चाहिए कि किन-किन लोगों ने रूपया निकाला और कितना रूपया निकाला? सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जो सूती दी गई है, वया वह संपूर्ण है? यदि सूती पूरी नहीं है तो कब तक पूरी सूती प्रकाश में आएगी? सरकार की तरफ से इस पर जवाब आना चाहिए। वया इस बात का आंकलन किया गया है कि दुनिया भर में भारतीयों का कितना धन कहां-कहां गया है और किसका है?

जबकि पिछली कांग्रेस सरकार ने थोड़ा-बहुत कुछ बता दिया था कि इतना रूपया विदेश में है और इतना काला धन है। नाम बताने पर उन्होंने भी चुपची साध ली थी। सदन में उस समय भी बहुत जोर दिया गया। वया सरकार सदन को समय-सीमा बताएगी कि विदेशों में हिंदुस्तान का जो काला धन है, वह कितना है और किस-किस व्यक्ति का है? अब तक आपने इस दिशा में वया प्रयास किए हैं? इस बात की वया लगातार पूरे देश में हो रही है, सदन में हो रही है और कहीं-कहीं विधान सभाओं में भी यह मुद्दा उठा है। अभी तक इस पर कहां तक कार्रवाई हुई है और कितना पैसा है, यह सदन को बताया जाना चाहिए? इस काले धन को कब तक वापस लाने का आपका इरादा है? इसकी भी आपको समय सीमा बतानी चाहिए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि 120 लाख करोड़ रूपये का काला धन है। यह दावा बीजेपी के नेता का है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का कहना है कि दस लाख करोड़ रूपये का काला धन है। आपके सबसे ज्यादा समर्थक, इस सरकार के बनल में साधु, सन्यासी होकर भी, जो बाबा रामदेव हैं, वे काला धन वापस लाने की मुक्ति चला रहे हैं। वे बिल्कुल सरकार के कड़ीबी माने जा रहे हैं। बाबा रामदेव का दावा है कि देश का 400 लाख करोड़ रूपया काले धन के तौर पर विदेशों में जमा है। अब आप सोचिए कि यहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है, सिंचाई के पूरे साधन नहीं हैं, बिजली हम दे नहीं पा रहे हैं। जितनी लागत इन विकास के कामों में आयेगी, उससे कई गुना ज्यादा पैसा विदेशों में काले धन के रूप में जमा है। आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। रोजाना समाचार-पत्रों में लिखा जा रहा है और हर तरह के मीडिया में यह आ चुका है और यह वया का विषय है। यह विषय गाँव-गाँव तक पहुँचा है और पहुँचेगा। इस देश का कितना काला धन विदेशों में जमा है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और यह जानकारी आपको है। इसका सही-सही अनुमान किसी सरकार या साथी ने नहीं दिया है। लगभग 80 लाख करोड़ रूपये का काला धन विदेशी बैंकों में जमा है। वर्ष 1951 के बाद से हर साल करीब 10 फीसदी काला धन बढ़ जाता है। देश की कुल जी.डी.पी. का 50 फीसदी काला धन समानान्तर अर्थव्यवस्था चला रहा है। देश की यह हालत है कि यहाँ एक सामानान्तर अर्थव्यवस्था चल रही है। काले धन की जाँच की माँग कई बार उठी है, यह माँग संसद में भी उठायी गयी है। सरकार ने आश्वासन दिये, लेकिन कुछ ठोस काम और कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए यूपीए सरकार भी जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित करने के लिए कहा था। उसे सरकार ने गठित किया, यह अच्छी बात है।

चुनाव के दौरान हर सभा में प्रधानमंत्री जी ने, मोदी साहब ने कहा था कि हम सौ दिन में ही सारा का सारा काला धन विदेशों से वापस ले आयेगे। अब तो छह महीने हो गये हैं। अब तो और ज्यादा समय होता जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। उन्होंने कहा था कि विदेशों में जमा काले धन की पाई-पाई हम वापस लायेंगे और हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रूपया जमा कर देंगे। आपके प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में कहा था कि विदेशों में जितना भी काला धन जमा है, पाई-पाई पैसा हम वापस लेकर आयेंगे और 15-15 लाख रूपया हर परिवार को बाँटेंगे, हर परिवार को दे देंगे। इसका वया मतलब है? इस आश्वासन पर देश की जनता ने खूब सोचा कि 15-15 लाख रूपया मिलेगा और सारे वोट इन्हें दे दिये। जो वोट कभी हमारे खराब नहीं जा सकते थे, 15 लाख रूपये के तालच में वे भी चले गये। नौजवानों के वोट इसलिए चले गये कि हमें रोजगार, नौकरी की गारन्टी मिल गयी। ऐसे नारे देकर, असत्य बोलकर आपने सरकार बना ली है, यह बात तो ठीक है, लेकिन आप यह समझिये कि ऐसी सरकारों की उम्र ज्यादा नहीं होती है। आप सरकार चलाते जाइये, वयोंकि, आपके पास बहुमत है, लेकिन आप जनता के लिए वया कर रहे हैं? आप जनता से किया हुआ वायदा पूरा कीजिए। अगर आप वायदा पूरा कर देंगे तो हो सकता है कि जनता आप पर दोबारा विचार कर ले, वरना हमेशा के लिए साफ कर देगी। हम और सांसदों को बता रहे हैं, ये तो बैठ गये हैं, मिनिस्टर बन गये हैं, इनका वया जाता है, इन्होंने तो अपना सम्मान कर लिया है और जो भी करना होगा, वह कर लेंगे। आप साधु-सन्यासी लोग वया करोगे? आप बताइये कि वया करोगे? हम आपसे यह पूछना चाहते हैं। ये तो मंत्री बन गये हैं। आपने यह आश्वासन देश की जनता को दिया था। आपको देश की जनता ने प्रधानमंत्री बना दिया है। यह पूरा का पूरा असत्य का पुलिन्दा है, आपने देश की जनता से असत्य बोला है। अब तो छह महीने हो गये हैं, आपने तो 100 दिन की बात कही थी। आपने ऐसा आश्वासन वयों दिया और 100 दिन का वादा वयों किया? आश्वासन दिया और सौ दिन का वायदा किया। महत्वपूर्ण भूमिका आपकी भी तो है। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप पहले से हैं। हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं और हमें आप अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत सारी बातों पर हम एक रहे और कई मामलों में साथ रहे। आप जो कह देते हैं, वह करते भी हैं। हमें विश्वास है और यह सच है लेकिन प्रधान मंत्री को यह जवाब देना पड़ेगा कि अदालत को ही नहीं, संसद को भी आपको बताना पड़ेगा कि कितने काले धन की वापसी हो गई है या कब होगी? अमेरिका ने विदेशी बैंकों में जमा काला धन वसूलने के लिए वया किया था, वया आप नहीं कर सकते हैं? अमेरिका ने सारा काला धन बाहर निकाला और वह सरकार के पास आ गया। यदि आपको पता नहीं है तो पता लगाइए कि अमेरिका ने वया किया था। जब अमेरिका निकाल सकता है तो आप वयों नहीं निकाल सकते? इस काले धन के कारण ही महंगाई है, इसी से भ्रष्टाचार है, इसी से अमीरी-गरीबी के बीच की खाई बढ़ी है। इसी से हमारे बच्चे पढ़ाई-लिखाई में, गरीब लड़के अच्छे स्कूलों में नहीं जा सकते। आज तो कई तरह के स्कूल हो गए हैं। एक ऐसे स्कूल हो गए हैं कि जिनमें बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उद्योगपतियों के बच्चे पढ़ते हैं, मिनिस्टर्स के हैं और कुछ एम.पीज़ के बच्चे भी किसी तरह पहुँच जाते हैं लेकिन गरीब लड़के कहीं अच्छे कालेजों या अच्छे स्कूलों में पहुँच पा रहे हैं? नहीं पहुँच पा रहे हैं। यह सब उसी पैसे से हो सकता है।

पिछली यूपीए की सरकार और वर्तमान सरकार दोनों को पता था कि जिन लोगों का काला धन जमा है, उन लोगों ने पैसे निकाल लिये हैं। आपकी सरकार को भी पता था कि पैसा किन्होंने निकाला और पहले की सरकार को भी पता था कि पैसा किन्होंने निकाला। ... (व्यवधान) मैं दोनों सरकारों की बात कह रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार को भी पता है और इस बीजेपी की सरकार को भी पता है कि काला धन किसका है, कितना किसने निकाला है। इनको पता है और उन्हें इस सदन को बताना चाहिए। अगर इन्होंने गलती की तो वया आप भी गलती करेंगे? अगर इन्होंने गलती की तो आप वहाँ पहुँच गए और आप गलती करेंगे तो आप विश्वास रखाए, हमने बड़े-बड़े बहुमत देखे हैं, आप यहाँ आ जायेंगे। ऐसा नहीं है, जनता सब समझती है, आपको यहाँ से वहाँ पहुँचाया। आप गलती कर रहे हैं लेकिन यदि मेरी बात मान जायेंगे तो बने रहेंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो देश की जनता का ख्याल है।

एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल 14 हजार करोड़ रुपये इन बैंकों में जमा हैं। आपको तो पता ही है। मुझे पता है कि आपको पता है। टैक्स चोरी का कम से कम जितना काला धन देश में छिपा है, उसको सरकार कब तक निकालेगी, यह बताना चाहिए। हवाला के माध्यम से जिन देशों में कारोबार हो रहा है, कृपा करके उन पर सरकार कब तक रोक लगाएगी? यह करने में आपको क्या दिक्कत है? एक बार ऐसा हुआ कि मेरा दोस्त खड़ा था। उसके सामने हवाला से रुपया जा रहा था। कितना रुपया जा रहा था, यह पता है लेकिन यह नहीं पता कि कहां जा रहा है। बाद में धीरे-धीरे वह पीछे रखा गया। शायद उसको पता हो गया हो। इस तरह हवाला में यहाँ से पैसा जा रहा है। इस हवाला को बंद कर दीजिए। इसको तो आप कर सकते हैं। इससे सरकार को क्या है? यह जो जनता से तूटकर पैसा बाहर जा रहा है, इसे बंद कीजिए। राजनीति और मनोरंजन की दुनिया काले धन का इस्तेमाल पूरी तरह से कर रही है, यह किसी से छिपा नहीं है। सरकार को बताना पड़ेगा कि इस पर पूरी तरह से कितने दिनों में रोक लग जाएगी, मैं यह जानना चाहता हूँ। आप छोड़िये कि इस पर रोक कब तक लगेगी। काले धन का जितना पता आप लगा सकते हैं और जिसका आपको पता है, वह कब तक वापस लाओगे? जिनका काला धन है, इनके नाम सदन के अंदर जारी करने चाहिए। आपको नाम मिल जाएगा। हम लोग जनता में बोलेंगे कि इनका पैसा विदेश में है तो वह सब निकालेगा और अपने देश में आ जाएगा। इनमें से क्या आप करेंगे, इसका उत्तर ज़रूर सदन को देना चाहिए। देश की जनता जानती है और सबको पता है कि हमारा पैसा, काला धन विदेशों में जा रहा है और मुझे भर लोगों के हाथों में पूरी दौलत इकट्ठी हो रही है।

महोदय, मंत्री जी जिम्मेदार हैं, समझदार हैं, जानकार हैं और कभी-कभी हमारे सवालों का उत्तर भी दे देते हैं। कृपया आप आश्वासन दीजिए कि काला धन कब तक देश में वापस ला रहे हैं।

SHRI P. SRINIVASA REDDY (KHAMMAM): Respected Sir, at the outset, I would like to say that the issue of black money is being discussed in this august House for years together.

First of all, we have to see the difference between black money prevalent in India and the money sent out of India. It is the tax-evaded money and the Indian money outside India is not only tax-evaded money but also money which has been taken out of India's capital resources which needed for the development of India. So, it is not only tax evasion but treason too.

I appreciate the effort, which is being made by the present Government under the leadership of our bold Prime Minister Shri Narendra Modi ji about black money stashed abroad and how it needs to be brought back. Today, no political party can say that black money is not an issue; it has become a national issue. Who drives it, who is more sincere, who has more commitment is a different issue.

Recovering black money is a very strategic issue as the Indian Government has to make alliances with many countries for which we took no efforts at all so far. This Government can take these efforts because it has high level of influence with most of the countries. The credibility of this Government is high.

The Global Financial Integrity Organisation came out with a calculation that between 1948 and 2008, about \$ 500 billion which is about Rs.30 lakh crore has gone out of India. Most of it has gone out of India after India has liberalized the economy.

The important issue is why only Switzerland, Cyprus etc. countries can be tax havens. Why can India not be a tax haven? Forget chasing names and try to concentrate on our uncalculated money which has gone out of India. Please change our laws and make India as a "Tax Haven". Let all the black money in the world work for the prosperity of India. Even if our country's black money comes back, that is a huge amount for us. The only way is to make India as a tax haven and encourage to bring it back.

To keep tight vigil on depositors, the Government should frame some serious guidelines to monitor money inflow and outflow which helps to control the black money. Government should expedite the legal process in delivering justice in some tax evasion cases or in any case which is relating to money in a time-bound manner. There should not be any scope for influencing the judiciary and fix in legal issues.

With these words, I conclude my speech.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAI AH NAIDU): Hon. Chairman, Sir, at the end of the debate, the hon. Minister of Finance will be, responding to the various points made by different sides of this House, right from the leader of the Congress Party which is the largest Opposition Party to Shri Mulayam Singh Yadav to Shri P. Srinivasa Reddy who have made various points. I have made a note and I will be passing it on to the hon. Finance Minister.

My purpose of intervention at this stage is to put certain things straight before the House, and through the House, to the countrymen also. Sir, when hon. Members have given notice and they wanted even the Business to be put on hold, and this issue to be taken up on priority basis, I thought, there will be very constructive and meaningful suggestions. Some of the Members may have some important information which they will be able to share with the House so that the Government can start taking up further action. But to my disappointment, I didn't have. ... (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Let the debate be over. ... (Interruptions)

SHRI M. VENKAI AH NAIDU: I am not replying to the debate, the Finance Minister would reply. ... (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Wait for the debate to over. ... (Interruptions)

SHRI M. VENKAI AH NAIDU: Shri Asaduddin, okay. You will be making some good points. Let us hope for good points. ... (Interruptions) Sudip da, it all depends on both sides. I want the House to discuss this serious issue in a very serious manner. But unfortunately, efforts were made to derail this debate from the beginning itself. My friend and the Leader of the Congress Party, Shri Kharge, whom I hold him in high esteem because of his experience, initially suggested that the BJP manifesto stated that the Government would bring back black money within 100 days. I have been the Party President earlier, now I am also the Member of the Parliamentary Board, and also one of the Members who finalized this manifesto. We very

well remember; we are not that much immature to say that the entire black money can be brought back within 100 days. ...(*Interruptions*)

I am quoting from the manifesto of the BJP of 2014 – the manifesto is with me – with the permission of the Chair, I quote. It is stated in the manifesto that by minimizing the scope for corruption, we will ensure minimization of the generation of black money. BJP is committed to initiate the process of tracking down and bringing back black money stashed in foreign banks and off shore accounts. We will set up a Task Force for this purpose, to recommend amendments to the existing Acts, or enact new laws. The process of bringing back black money to India that belongs to India will be put in motion on priority. We will also proactively engage with foreign Governments to facilitate information sharing on black money. This is what is contained in the manifesto.

**श्री मुलायम सिंह यादव :** आपने बयान दिया है, ... (व्यवधान) आप ये बताइए कि आप कालेधन को कब तक वापस लाएंगे? ... (व्यवधान)

**श्री एम. वैकुण्ठय्या नायडू :** आपने सही कहा, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। उस समय के वित्त मंत्री, पूणब बाबू ने हाउस में क्या कहा, जो आप बता रहे हैं। उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी शेयर करूँगा। There is no need to get excited or accuse each other. Everything is available to all of us. You can criticize; there is nothing wrong. It is the duty of the Opposition to criticize the Government, the party; and it is the duty of the Government to explain to the House, and also to the people. This is what has been said in the manifesto. What did we do after saying it in manifesto? We came to power on 26<sup>th</sup> May, the day the Prime Minister was chosen. On 27<sup>th</sup> May, after the formation of the Cabinet, the Union Cabinet met on 27<sup>th</sup> May, 2014. I am the Member of the Union Cabinet. Cabinet approved setting up of a Special Investigating Team headed by a former Judge of the Supreme Court of India, Justice M.B. Shah to unearth black money stashed abroad.

Justice Arijit Pasayat will be the Vice Chairman of the Panel. The members of the High Level Committee will be the Secretary, Department of Revenue, Deputy Governor, Reserve Bank of India, Director, Intelligence Bureau, Director, Enforcement Directorate, Director, CBI, Chairman, CBDT, Director General, Narcotics Control Bureau, Director General, Revenue Intelligence, Director, Financial Intelligence, Director, Research and Analysis Wing, Joint Secretary, CBDT . They have been given this responsibility.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): When was this Committee set up?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: The Cabinet approval was given on 27<sup>th</sup> May.

PROF. SAUGATA ROY : The order was made on 4<sup>th</sup> July, 2014. You took so much time to constitute the Committee. ...(*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Saugat Royji, you have got your dates wrong.

PROF. SAUGATA ROY : I have got a Note submitted to the Standing Committee on Finance. The terms of reference of SIT will be as per the order dated 4.7.2011 and the order was made in July. ...(*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: The new Government was sworn in on the 26<sup>th</sup> of May. The Ministers assumed office on 27<sup>th</sup> of May. The first Cabinet Meeting was held on the 29<sup>th</sup> of May and in terms of the Cabinet decision, on the 29<sup>th</sup> of May itself the SIT was constituted. It started functioning in June. The entire list of account holders and all the data available with us was submitted to them in June. Some order may have been issued on 4<sup>th</sup> July. But the SIT has been functioning right from then.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I stand corrected about the date. My point is, we have to judge the Government by its intention, by its action and by its sensitivity. Within three days after coming to office, we took such an important decision and decided to move forward. What I would like to say is that the same thing could have been done by you. You may say, 'what is it that you have done by constituting a Committee?' You could have done it yourself when you were in Government. ...(*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): What concrete action did you take in these six months? ...(*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Mr. Premachandran, please have patience. You have also committed a sin of supporting that Government. Please try to understand. ...(*Interruptions*)

**श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) :** सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम दिया था कि इसे 15 दिन के अंदर करना है, ... (व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Salimji, please have patience. ...(*Interruptions*)

सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह हो, आदेश हो ... (व्यवधान) आपकी बीमारी ने उनको भी पकड़ लिया, मैं क्या करूँ? ... (व्यवधान) दोनों बैठकर ही बोलते हैं। ... (व्यवधान) You are also my brother, he is also my brother. I am trying to convince and console both the brothers. I don't make any difference between you and him.

माना कि हमने सुप्रीम कोर्ट के कहने के कारण से इसे किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर वर्ष 2011 में कहा। वर्ष 2011 से 2014 तक आप ही सलाह में थे, आप ही के लोग मंत्री थे, फिर आप लोगों ने सर्वोच्च न्याय स्थान का आदेश क्यों नहीं माना? वह केवल सर्वोच्च न्याय स्थान का आदेश नहीं, तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री एवं वर्तमान में राष्ट्रपति जी हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। He is a most respectable person.

**श्री मुलायम सिंह यादव :** आप इसका जवाब दीजिए कि पैसा कहाँ चला गया और किसने निकाला? ... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** जब मंत्री जी जवाब देंगे, तब कहेंगे।

â€¦ (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** माननीय सदस्य, जब वित्त मंत्री जी बोलेंगे, तब उस समय जवाब देंगे। अभी आप धैर्य से सुनिए।

â€¦ (व्यवधान)

**श्री एम. वैकर्या नायडू :** उस समय यह मामला गंभीर मामला बन गया। यह पब्लिक डिस्कशन का मामला बन गया। यह पब्लिक डिस्कशन का मामला बन गया। पब्लिक डिस्कशन के बाद, कुछ लोग कोर्ट में भी गए और मीडिया में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई। जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, ठीक है। हमारे नेता श्रीमान् आडवाणी जी ने इसको पूरे देश में मोमेंटम दिया, उन्होंने एक कैम्पेन चलाया। उसके बाद देश भर के अखबारों में आर्टिकल्स आने शुरू हो गए। कुछ बुद्धिजीवियों ने मिलकर एक टास्कफोर्स बनाया और टास्कफोर्स ने भी एक रिपोर्ट दी। इस बीच में आप लोग लाइटर-वे में, मजाक में कह रहे हैं, एक ने कहा 25 लाख रुपए, एक ने कहा 30 लाख रुपए, एक ने कहा 20 लाख रुपए,...(व्यवधान)

Shri A.P. Singh, former Director of CBI, during that period, in an official meeting, had disclosed that there is Rs. 25 lakh crore of black money. This was the statement given by a CBI serving Director at that time. मैंने हाउस में खड़े हो कर कहा कि CBI is a premier institution. You are using it or misusing it, that is a different point. We have discussed it enough. The point is, when the CBI Director says Rs. 25 lakh crore, normally others will definitely take note of it. We have asked the Government. The Government have kept quiet about that. The then Finance Minister has also issued a White Paper. I have the White Paper with me; that is 'The National Common Minimum Programme of the Government of India' released on Thursday, May 27, 2004. In that also, there is specific mention about taking special schemes to unearth black money and they will be assessed and they will be brought back. वह भी आपने कमिन्टमेंट किया, आपने कोई गलती नहीं की। आपके जमाने के सर्विंग सी.बी.आई. डायरेक्टर ने कहा कि भारतीय नागरिकों ने विदेशी बैंकों में 25 लाख करोड़ रुपए जमा किए थे। यह भी हुआ कि सदन में यह इश्यू दो-तीन बार उठाया गया था। बाद में, पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन और फिर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया, आदेश आने के बाद भी आप इस विषय पर एक कदम आने नहीं बढ़े।

दूसरा, जब आप से पूछा गया तो मेरे पास रिप्लाय है, डा. मनमोहन सिंह जी ने कहा कि the Finance Minister while replying to the debate on the Finance Bill yesterday has specifically dealt with this aspect. He said that the action on it had already been started. That is what they have said it also on the floor of the House in respect of unearthing the black money. I am quoting the then Finance Minister. This is on 29<sup>th</sup> July, 2009. In respect of unearthing black money the Finance Minister suggested that we should initiate action within 100 days. 100 डेज वहां से आया।...(व्यवधान) This is in the proceedings of the House. The point is, then, and now also, 100 days means that action will be initiated in 100 days....(Interruptions)

**माननीय सभापति :** माननीय सदस्य अपने स्थानों पर बैठ जाएं।

â€¦(व्यवधान)

**माननीय सभापति :** आप इनकी बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। आपका अक्सर आएगा तो आप बोलिएगा।

â€¦(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIHA NAIDU : Undoubtedly, corruption was a main issue in the election. There is no doubt about it. Then the number of scams that have taken place in between the last 10 years, they were highlighted. Naturally, the issue of black money was also on the top of the agenda. Then the people wanted immediate action to bring back the black money. They did not believe that Government. They believed this Party and then gave a mandate in favour of this Party. I am admitting it. ...(Interruptions) People have already given their mandate. Let us wait for some time. ...(व्यवधान) मुलायम सिंह जी, आप सिलियर मेंबर हैं। आप इस उम् में इतना उत्तेजित न हों।...(व्यवधान) मैंने आपकी बात को शांति से सुना है।...(व्यवधान) आपने जो प्वाइंट्स बताए हैं, उन्हें मैंने लिखा लिया है। मैं इन्हें अरूण जी को दूंगा, वे इनका जवाब भी देंगे। आप निश्चित रहिए, हम यहां से भागकर जाने वाले नहीं हैं। हम पांच साल पूरा करेंगे और आगे भी 5 साल पूरा करने की संभावना ज्यादा है।

Sir, being a Parliamentary Affairs Minister, I do not want to score points also because I have other responsibility. My point is this. Why I am trying to say this is that the intention is that you must take action. I have already told about our first action that an SIT was constituted. The Finance Minister will tell you in detail about our second action. He has started discussing with different countries. Thirdly, the treaties that have been agreed upon and then entered upon by successive Governments including your Government, they all have a secrecy clause. That has been agreed upon by you. Your Finance Minister told this on the Floor of the House...(Interruptions) आप नहीं थे, आप बाहर से समर्थन कर रहे थे।...(व्यवधान) आप सरकार में कभी नहीं रहे लेकिन सरकार को सुबह, दोपहर, शाम ऑक्सीजन आप ही देते रहे।...(व्यवधान) आपकी दया के कारण यह सरकार चली।...(व्यवधान) Let us have a healthy and friendly debate. You can criticize; you can accuse; and you can expose if I have done something wrong or my Government has committed some big scams, etc. You have got every right and there is time for that.

Coming back to the issue, my third point is that the hon. Prime Minister himself has taken up the issue in a big way in G-20. He spoke in that Summit also. He is trying to sensitize other countries also. Now, every country has realized it.â€¦ (Interruptions) Hon. Members, this is not fair sitting and making running commentaries. It is a very bad habit. Children will remember us for ever of such a behaviour....(Interruptions)

I am quoting from the speech of former Finance Minister. He said:

"I had responded in this very House itself that we had difficulty. We had got certain information but we got this information under the condition that we would not disclose that information even to our sovereign Parliament. Otherwise it would not be possible for them to give the information. Every country has its own rules. Certain countries have their own banking secrecy rules, Switzerland is well known for it. They have agreed to share this information provided there is a legal framework and it is required only for the purpose of tax collection."

This is what hon. Finance Minister had told in the House on 29<sup>th</sup> June, 2009. ...(Interruptions) Hon. Member, you are not authorized to speak. When you get a chance you can definitely say whatever you want. I and Arunji, both are here today and tomorrow or even for a longer period also....(Interruptions) My point here is that subsequently the Ministry has engaged different countries across the globe about the need to have mutual agreement, about to reform the entire financial system across the globe and the way forward. So they got names. Their names are not kept secret. This is another propaganda going on. नाम आया, नाम क्यों नहीं देते, नाम दें और उनकी छुट्टी करें, यह होता है। मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। The then Finance Minister, Pranab babu rightly said in the House and we are trying to come out of that situation. My third point is that what we did is when we got the names; the names were promptly given to the Special Investigation Team. What else you want us to do. Being a senior most Member Mulayam Singhji has said नाम पार्लियामेंट को बताएं, देश को बताएं, वे लोग बदनाम हो जाएंगे, सरकार का काम हो जाएगा, पैसा वापिस आ जाएगा। परपज़ क्या है? क्यों मुलायम जी भी इतने विवक्षित हैं? मुख्य काम पैसा वापिस लाना है।

दूसरा, जिन लोगों ने गलती की, उन्हें सजा दिलाना, यह मुख्य परपज़ है। इस परपज़ को एचीव करने के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं, उस समय वित्त मंत्री जी ने कहा, वह प्रॉब्लम्स अभी भी मौजूद हैं। उन

पुंल्लम्स से बाहर आने का क्या उपाय है? हमारे मंत्री जी ने बीच में एक स्टेटमेंट दिया, एक स्टैंड दिया, पब्लिकली भी कहा। कुछ लोग कह रहे थे कि फिर नाम कभी पब्लिक नहीं होगा। वे नाम कब पब्लिक होंगे? जब इन्वॉयसी करके चार्जशीट फाइल करेंगे तब नाम आटोमेटिकली कोर्ट द्वारा पब्लिक हो जायेंगे। पूरे देश की जनता को मालूम हो जायेगा। आप यह भी देखिये कि काम कर रहे हैं या नहीं? चार्जशीट क्या है? सरकार की नीयत पर शंका है तो आपको आने वाले दिनों में मालूम पड़ जायेगा। नाम मिला, इन्वेस्टीगेशन चल रहा है और इन्वेस्टीगेशन के बाद चार्जशीट फाइल करेंगे या नहीं करेंगे? क्या उन्हें बताने के लिए कोशिश करेंगे? जैसा पहले किया, उस समय भी आपको मालूम है। पैसा विदेशी बैंकों में था और हम लोगों ने बैंकों का खाता सीज करके रखा। उसके बाद हमारी सरकार ने ही उन खातों को ओपन करने का मौका दिया। यह सरकार भी क्या ऐसा करेगी? ऐसा किया, जैसा आप बता रहे हैं। आप लोग भी बदनाम हो जायेंगे। जब काम बुरा होगा, बदनाम होना सामान्य रूप से होगा। मेरा कहना है कि यह सरकार अभी-अभी आयी है। यह अच्छा काम कर रही है। पूरे देश में उसे प्रस्तुत कर रही है। आपने देखा कि चुनाव के बाद, आप कह रहे हैं कि आपने... \* दिया। कुछ लोग कह ऐसा भी नास दे रहे थे। उसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। Shri Sudip Babu, with all respect I am telling you this. The Prime Minister of the country is a respectable figure. The leaders of different parties are also respectable figures. We can criticise each other and we can expose each other if there are points. वैसे जिस प्रधान मंत्री को पूरा देश प्रेम कर रहा है और विदेशों में भी इतना स्वागत हो रहा है। साथ ही साथ आपने अभी देखा, हम महाराष्ट्र में गये, हरियाणा में गये। ... (व्यवधान) Democracy functions on numbers. ... (Interruptions) बाइ-इलैवशन क्या है? सुरेश बाबू आप मेन इलैवशन देखिये। ... (व्यवधान) मेरा कहना है कि परसेंटेज सिस्टम में परिवर्तन लाने के लिए कुछ उपाय हैं, तो बताइये। हम उस पर चर्चा करेंगे। जब तक 50 परसेंट नहीं आयेगा, किसी को नेता नहीं बनाना, ऐसा नियम लाना है, तो आप चर्चा कीजिए। हम उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। देश की जनता ने कल अखबारों में देखा होगा कि 72 per cent of the people of India are favouring the Prime Minister. That is the latest survey. You must have seen what happened in Haryana. In Haryana, my Party is not strong. We do not have that much organizational base. I had been to each and every main district of the country in the last 25 years. ... (Interruptions) सुदीप जी, आप लोग क्यों इतना डिस्टर्ब हो रहे हैं? आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। बंगाल में उस कारण से जमीन नीचे खिसक रही है। ... (व्यवधान) वह इश्यू नहीं है। ... (व्यवधान)

**श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर):** आप खूब मत देखिये। ... (व्यवधान) आपका जैसा है, वैसा ही रहेगा। ... (व्यवधान) अगर खींचतान हुआ ... (व्यवधान)

**SHRI M. VENKAIAH NAIDU:** Okay, I will wait. We will meet shortly in Bengal, whenever an opportunity comes. If your word prevails and it proves correct, then fine and I salute you. If my word and people's will prevails, then fine, nothing wrong. ... (Interruptions) मैं बतपन से स्वप्न देखा रहा था कि श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधान मंत्री बनेंगे, तो वह स्वप्न साकार हो गया। उसके बाद मैंने यह स्वप्न देखा कि इस देश में बी.जे.पी. को अकेले में बहुमत मिलेगा, तो वह बहुमत संभव हो गया। ... (व्यवधान) मैं अभी स्वप्न देखा रहा हूँ, मुम्बई हो गया, कोलकाता भी अच्छा है, वहां भी जाना है। ... (व्यवधान) आप में से जो साथ देना चाहते हैं, वे दीजिए। ... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** वैक्या जी के अलावा किसी और माननीय सदस्य की कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

... (व्यवधान) \*

**श्री एम. वैक्येय्या नायडू :** यहां थोड़ा ज्यादा बोलकर, थोड़ा स्ट्रॉंग वर्ड यूज करके चुनाव जीतना आसान है तो फिर जीत आपकी होगी। मगर मेरा कहना यह है कि सच क्या है? What is written on the wall? How is the response coming across the globe? What has happened in Madison Square? What has happened in Sydney? ... (Interruptions)

**16.00hrs**

All right, I wish you best of luck. We cannot stop the sun rays by raising our hands like that. By stopping my President's rally, you are not going to succeed in West Bengal. Please try to understand this. People are very intelligent. They have become intelligent after so many years of rule by all of us, mostly Congress Party, then followed by NDA and then followed by UF, the United Front for some time and all. People have now expectations. It is a fact.... (Interruptions)

This is my last point. I do not want to take much of your time. The last point is, the expectations are very high. I do agree because people feel, yes, this man can deliver; and he can do. Modi is the remedy. That is what the people of India are thinking. Modi is "Decisive, Dynamic and Development-oriented. That is the expectation. So, they are expecting that everything will happen, and also they will happen quickly. That is what the expectation of the people is. That is the challenge before us. So, we have to work hard. We have to walk an extra mile and we are trying our best. And, we have the best people in our Government. We have capable Ministers, and I see my Finance Minister, the way in which he is dealing with things in the country... (Interruptions)

Bear with me, please. ... (Interruptions) Black money is not generated in these last six months. Who was in power all these years? It is in everybody's knowledge. I do not want to get into all these things. I do not want to derail the debate. I have been to Barcelona. There was a World Smart City Congress.... (Interruptions) I brought the prestige back and I lost one of the bags. In the inaugural conference, I was told that there were representatives of 240 companies from 180 countries or so, including 140 representatives from local self-help governments. After I spoke I saw the amount of enthusiasm and inquisitiveness among the people about India. I am not saying about BJP or about NDA alone. I am saying about India because in the entire world now India is rising in their eyes and people are now recognizing it and respecting it.

So, my request to all of you is this. I am happy that Madam Sonia Ji is also here during this important discussion. She is the President of a major Opposition Party. Also, other leaders are here. Mulayam Singh Ji is also here. Sudip Babu is also here. We should really compete now with coming with new and good ideas and then tell the people इनकी ये गलती थी, हमारे पास बेहतर आइडिया है, इस आइडिया के कारण देश और आगे बढ़ सकता है। This should be the competition in the coming days and this should be the agenda for the country--development, development, development and nothing else. People want it and we cannot be watching.

You had been in power. I had been in the Opposition. I also had been in power and I have been in power now. Then Trinamool Party is in power in some place. Then, AIADMK is in power in other State. Communist Party is also fortunately still there in power in one State. They are in power in one of the States, that is, in Tripura, in the North-East. So, there is no way where people can escape from responsibility. What we are saying here, have you done it there in your State? Have I done it in my Government here? This is being closely observed by all the people. So, there is no problem on that count. Let us have a healthy debate, discuss the issue, come with much more good ideas and easy solutions. Because you have the most experience because you have been in power for long, long and also in position. So, you may be having better ideas. You give the ideas. My Government is open to take these ideas. We have no problem.

The Prime Minister has already said that we must all work as a team India and we will be working together. We will be taking your good and well intentioned advices also and then moving forward. I, for myself, feel that the Finance Ministry which is proactive in this matter has to engage with the other countries and see to it that these treaties are arrived at the earliest stage, then these investigations are completed in a speedy manner and the matters are taken to the court. The courts are, of course, independent and they will take decision at the earliest so that the people, who are involved in it, get the needed punishment. Then, we will be able to get back our money.

My last point is regarding the issue raised by Shri Mulayam Singh. There is a figure, which is given in the White Paper, which was raised in the Parliament. It was clearly mentioned by the then Finance Minister after this information had gone out that the number of accounts and the amount of money stashed in Swiss banks has come down considerably. It means that it has been siphoned off and moved to some other tax havens. That being the case, we must act fast. We should have acted earlier. There is no meaning in criticizing it. That part is over. Elections are over. Now, we are in the Government. So, it is our duty to take quickest possible action and my Government is really engaged in that. We need the cooperation of one and all to do it with better ideas and support for the actions of the Government. It is in the interest of the country and the people at large. This is what I want to submit to the House.

**श्री महिलकार्जुन खड्गे (गुलबर्गा) :** सभापति जी, इससे एक रंग मैजेज जाएगा, जो श्री नायडू जी ने कहा कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहीं सौ दिन नहीं लिखा गया है और आप यहाँ सौ दिन की बात करते रहे तो वे अपना मैनिफेस्टो निकालकर भी बताएं। लेकिन हमने जो डेटवाइज़ कोट किया था, उस वक्त जो बी.जे.पी. के अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी थे, उन्होंने स्वयं कहा था कि हम सौ दिन में पूरा काताघन वापस लाएंगे और उसका फायदा सभी को देंगे। उस रेफरेंस से हमने आपको डेटवाइज़ बताया और आपने भी किसी न किसी जगह कहा था, मैं उस जगह का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि 16 लाख करोड़ रूपए की ब्लैकमनी है। अब आप खुद ही ऐसा बोल रहे हैं और ऐसा आपके प्रेसीडेंट ने बोला है और आपने हम पर यह कहते हुए पलटवार किया कि आपने स्टडी नहीं किया, आपने नहीं बोला, आपके पास तो 21 मई का पिछली सरकार का व्हाइट पेपर है, वया-वया किया गया, वया-वया स्टेप लिये गये, वया मैं उसे फिर से पढ़ूँ? ... (व्यवधान) इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ऐसा रंग मैजेज नहीं जाना चाहिए। लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए।

We had approached 22 prioritised countries jurisdiction during 2009 and 25 new countries jurisdiction during 2012; entered into Tax Information Exchange Agreement (TIEA), the lists of which are furnished hereunder; the number of countries communicated with during 2009 was 22; and the countries communicated with during 2012 were 25 in number.

The current status of negotiation with these countries is as follows: negotiation completed with 20 countries; TIEA signed with 14 countries; and entered into force with 14 countries.

ये सब प्रयास किये गये हैं, डाक्युमेंट आपके सामने है, इसके बावजूद भी कहा गया कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, जिन नेताओं ने यहाँ पर मुद्दा उठाया, उन्होंने कुछ सजेज़न नहीं दिया। यही तो सजेज़न है। आपके पास व्हाइट पेपर का जो पहला नम्बर पेज है, जिसमें पाँच मुद्दे हैं। उसके बाद वीरप्पा मोदली जी ने अपने भाषण में बहुत से सुझाव दिए। इन सबको नजरअंदाज करके कह रहे हैं कि कोई सुझाव नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टिव सजेज़न नहीं है। यह कहना अच्छा नहीं है। 100 दिन में पैसा ताने का आपका वायदा है, आपके अध्यक्ष का वायदा है और आप भी साठ लाख करोड़ रूपए की बात कर रहे थे, वह सब पैसा आप लेकर आइए, उसके बाद मालूम होगा। जो चीज नहीं हो सकती, जिस चीज के लिए कानून एवं प्रोसीजर के तहत वक्त लगता है, आप उसकी विन्ता मत कीजिए। वया आपकी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है, पहले के लोगों ने ही किया है? पहले पिट्सबर्ग, लंदन, आस्ट्रेलिया आदि जगहों पर विदम्बरम जी गए। वया वहां निगोसिएशंस नहीं हुए, बातचीत नहीं हुई? जैसे मोदी जी ने आस्ट्रेलिया जाकर बात की, वैसे ही हमारी पार्टी के हर नेता, प्रधान मंत्री से लेकर अन्य सभी लोग जब वक्त मिला, तब बात करते आए हैं। यह चीज आपको मालूम है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आइन्दा ऐसी गुमराह करने वाली बात मत कीजिए। जनता को यह मालूम है, पहले आपने जो वायदा किया है, उसे निभाइए... (व्यवधान)

**श्री एम. वैकेर्या नायडू :** इसीलिए जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया, आपके ऊपर विश्वास नहीं किया। आपने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ... (व्यवधान) हां, पांच साल के बाद देखेंगे। ... (व्यवधान) धैर्य रखाए। ... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** अब आपस में सवाल-जवाब मत कीजिए।

â€¦! (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** श्री मोहम्मद सलीम, आप बोलिए।

श्री मोहम्मद सलीम के अलावा किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

... (व्यवधान) \*

**श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) :** सभापति महोदय, मंत्री महोदय बहस के बीच में इंटरवेंशन किया ताकि मामला फिर से ट्रैक पर आए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अंत तक वह विषय पर आए कि नई सरकार किस तरह से कोशिश करे, जल्द से जल्द एक्शन ले, पहले जो हुआ, हुआ। लेकिन बीच में बहुत सी राजनीतिक बातें हुईं। हमें ऐसा लग रहा है कि लोग चुनाव में इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, लेकिन सरकार सरकार में रहती है, वह बदलती नहीं है। यह आज के मंत्री ही नहीं बोल रहे हैं, पुराने मंत्री भी यही बोलते थे, इसलिए आप देखेंगे कि काला धन का मामला बहुत गंभीर मामला है, लेकिन वर्षों से जो बहस हो रही है, सरकारी पक्ष एक बात बोलता है और विपक्ष दूसरी बात बोलता है। आज भी मंत्री महोदय ने उसी व्हाइट पेपर का जिक्र किया, जो व्हाइट पेपर इसी सदन में ताकर काला धन के मामले को व्हाइट-वाश करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उसमें सिर्फ रंग बदलने की कोशिश की जा रही है। पूरे देश के लोग उस पुराने गीत की पैरोडी गा रहे थे - कोई लौटा दे मेरा लुटा हुआ धन, तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं हूँ, 56 इंच की छाती है, अब हम पैसा लौटाएंगे। लोगों ने भरोसा किया। अब सरकार की जिम्मेदारी है।

**16.13 hrs (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)**

हमें पूरा यकीन है कि हम यहां चाहे जितना बहस कर लें, चीख-चिल्ला लें, आप चाहे जो बोल दें, काला धन कल वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हम सदन में चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम आपको वायदा याद दिला रहे हैं और हमें यकीन है कि सरकार को भी अपना वायदा याद है। जो बात हकीकत है, उसे मानना पड़ेगा। आप देखिए कि एन.डी.ए. सरकार और यू.पी.ए. सरकार में कितना अंतर है और कितना मेल है। अभी एक बात कही जा रही है, दोनों में अंतर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी यू.पी.ए. सरकार ने एसआईटी नहीं बनाई और एन.डी.ए. सरकार ने आते ही बना दी। अभी अरुण जेटली जी ने स्पष्ट किया है। कल तक कहा जा रहा था कि 26 तारीख को सरकार ने शपथ लिया और 27 तारीख को एस.आई.टी. बना दी गयी। अभी कहा गया है कि 29 तारीख को कैबिनेट की बैठक हुई, उससे पहले कैसे हो सकता है। गीते जी भी थे कैबिनेट मीटिंग में। लेकिन यह नहीं कहा जा रहा है कि यू.पी.ए. सरकार ने याचिका दी थी कि हम एस.आई.टी. नहीं बनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था कि एस.आई.टी. बनाना होगा। 23 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि 15 दिन के अंदर एस.आई.टी. बनाइए, वरना आप नाकाम रहोगे और हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में मॉनीटर्ड नहीं हो, इसलिए सरकार ने SIT बनाई। बार-बार यह कहना कि सरकार ने एसआईटी बना दी, सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, यह ठीक नहीं है, यह तो शुरुआत है, शारदा स्वैम के मामले में, हमारे राज्य में भी हम सुनते आते हैं कि एसआईटी बना दी गयी, लेकिन एसआईटी तो

शुरुआत होती है, उसके बाद वह मामला कहां तक पहुंचता, जांच से सत्वाई कहां तक आई, अपराधी कहां तक पकड़े गये, अपराध के आंकलन का क्या हुआ, यह सब देखना पड़ता है। खैर, यह काला धन बहुत गंभीर मामला है। वर्ष 1974 में वांचू-कमेटी बनी थी। वांचू कमेटी ने काले-धन के बारे में रिपोर्ट रखी थी। उसके बाद कई सरकारें आईं, लेकिन काला-धन वापस लाना, काला-धन जहां तैयार हो रहा है, उग रहा है, उसे रोकना, वह नहीं किया गया। माननीय मंत्री जी ने खुद कहा है कि कुछ लोगों ने याचिका दायर की, बुद्धिजीवियों ने टारक-फोर्स बनाया लेकिन अफसोस है कि जिन तीन व्यक्तियों ने याचिका दायर की थी उनमें से एक माननीय राम जेटमलानी थे, जिन्हें अपने सरकार बनाने के बाद भाजपा से निकाल दिया, क्योंकि रोल बदल गया, भूमिका बदल गयी। वे माननीय वित्त मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वे शुरु से ही इस मामले में गंभीर नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी नहीं, माननीय प्रधान मंत्री नहीं, लेकिन वित्त मंत्री के बारे में उनका शुरु से ही आरोप है कि उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे तब भी काला-धन के बारे में कुछ नहीं बोले और अब भी उस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। यह चर्चा यहां इसलिए की जा रही है कि सरकार इस मामले को ध्यान में रखे।

दूसरा बात है कि काला-धन देश का अपना धन है और अगर उसका हम सोर्स नहीं जानेंगे तो काला-धन तो आज भी बन रहा है। यह बिल्कुल सही है कि यह 6 महीने में पैदा नहीं हुआ है, यह आजादी के बाद से ही हो रहा है। वह धन हमारे किसानों और मजदूरों की मेहनत की कमाई है, काले धन के मालिक, चाहे वह भ्रष्टाचार से कमाया हो, चाहे वह गैर-कानूनी ट्रेड से कमाया हो, चाहे वह क्रिप्टोकरेंसी से कमाया हो। इसके तीन सोर्स हैं - क्राइम, कर्प्शन और कॉर्म्स। इन एक्टिविटीज को गैर-कानूनी तरीके से किया जाता है जिससे यह काला-धन उग रहा है, पैदा हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए सरकार को सख्त व्यवस्था बनानी पड़ेगी।

विदेश में जो धन है उसे वापस लाने के बारे में मंत्री महोदय ने भी कहा और व्हाइट-पेपर में भी यही कहा था कि हम वॉल्यूम उसका नहीं बता सकते कि कितना रुपया है। भाषण में हम बोल सकते हैं जैसे रामदेव बाबा जी बोल सकते हैं लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने 50 के दशक में इसी संसद में काला-धन के बारे में जोर-शोर से कहा लेकिन हम भी वॉल्यूम नहीं बता पाए, क्योंकि हमें लाखा-करोड़ों रुपयों का हिसाब आता ही नहीं है। लेकिन यह सही है कि काला-धन बन रहा है और विदेश में जा रहा है। पिछले 20-25 सालों में उदासीकरण के नाम पर यह काला-धन तेजी से विदेशों में गया। उस वक्त उदासीकरण के बारे में यह था कि जितना उदासीकरण हो जाएगा तो लाइसेंस-राज नहीं रहेगा, कोटा नहीं रहेगा, इंस्पेक्टर राज नहीं रहेगा, तो बिजनेस करना आसान हो जाएगा और किसी को रिश्ता देनी नहीं पड़ेगी। लेकिन पिछले 25 सालों में कर्प्शन का स्केल भी बढ़ा है और काला-धन का वॉल्यूम भी बढ़ा है। मनी-लॉन्डरिंग के कानून से छेड़छाड़ की गयी और यह मनी-लॉन्डरिंग अमरीका से आया और अभी हम और भी ज्यादा इस बारे में सीखा रहे हैं। यहां गैंगस्टर थे, माफिया थे जिन्होंने अपने रुपयों को काले से सफेद करने के लिए सेल्फ-सर्विस लॉन्डरिंग मेट बनाए थे। आज पूरे विश्व में मनी-लॉन्डरिंग हो रही है और हमने कानूनों को सही ढंग से लागू नहीं किया। ये जो पॉन्जी-स्कीम का रुपया है, उसके साथ भी मनी-लॉन्डरिंग का मामला जुड़ा हुआ है। फिर आप देखें हवाला शैकेट है और हमारे देश में यह घोटाला बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। काफी लोगों का उसमें नाम आया, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं हुआ, सब मामला रफ्त-दफा हो गया। आज भी हवाला देश से रुपये बाहर और अंदर लाने का एक बहुत बड़ा स्रोत है। चाहे स्मॉलिंग का मामला हो, ह्यूमन-ट्रेफिकिंग का मामला हो, आर्म्स-ट्रेड का मामला हो, ड्रग्स या नारकोटिक्स का मामला हो, इन सबके साथ हमारे देश का भविष्य और हमारे नौजवानों का भविष्य जुड़ा हुआ है। यह एक नैक्सस है और इसे तोड़ना आसान नहीं है। इसमें चाहे राजनीतिज्ञ हों, बड़े धनपते हों और राजनीतिज्ञ छोटे स्तर के नहीं, ऊंचे स्तर के हैं, व्हीमनल, माफिया ऊंचे स्तर के हैं। कुछ ऊंचे स्तर के बिग कॉर्पोरेट ह्युमिज और कुछ टॉप व्यूरोक्रेसी भी इसमें लगे होते हैं, इसलिए इसका निदान करना मुश्किल होता है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको दूर करेगी। डबल टैक्सेशन के बारे में पहली की सरकार ने जो कहा था, आज की सरकार भी वही कह रही है। आज की सरकार में मंत्री जावड़ेकर जी ने जुलाई, 2012 में कहा था-

"The Government is involved in a cover up. It is trying to justify this by saying it has signed DTAA's."

में दूसरे हस्तक्षेप को कोट नहीं कर रहा हूँ। जब उस वक्त के वित्त मंत्री ने यह कहा था कि हम डीटीए के कारण नामों को डिसक्लोज़ नहीं कर सकते हैं, उस वक्त बीजेपी के नेता श्री शशिंकर प्रसाद ने कहा था-

"The Government's argument that it can reveal the names to the Supreme Court but not to the public is baseless."

में सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ। यह इधर की या उधर की बात नहीं है। गार और डीटीए पर काफी चर्चा हो चुकी है। लेकिन उसको गलत तरीके से कोट किया जा रहा है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के अध्यापक और इस मामले में माहिर अरुण कुमार जी की बुक से कोट करना चाहता हूँ। यह अकेडमिक पर्सन हैं, किसी पार्टी से नहीं हैं।

"The UPA Government tried its best to see that the SIT for black money did not come into being. Similarly, the NDA also recently tried to scuttle the powers by asking for clarification in the order."

सिर्फ तरीका बदला है। डीटीए के बारे में है-

"The position is quite incorrect as the DTAA only ensures that tax paid on declared income is not paid in both the countries."

डबल टैक्सेशन अवाइडेंस का मकसद यही है।

"The Government have also claimed that the stolen data from the LGT Bank and from HSBC Bank was given under DTAA. However, this also cannot be true because the data was procured from the German and the French Governments by paying money to the former employees of these banks."

में इस विषय पर काफी कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। अब मैं मूल विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने एसआईटी के बारे में कहा कि उसे बनाने की बात कानून नहीं हुई थी। उसी प्रकार से यह कहा जा रहा है कि चुनाव में सौ दिन में लाने की बात नहीं कही गयी, यह बात यूपीए सरकार के मंत्री ने कही थी और वहीं से यह बात आयी थी। खड़गे जी ने भी अपने भाषण में कहा कि किस तरह से भाषण में कहा गया था। मैनिफेस्टो में सब बातें नहीं कही जा सकती हैं। हमने यह निर्णय लिया है कि हम एक सीडी रितीज़ करेंगे, जिसमें आज के प्रधानमंत्री और उस समय के स्टार कैम्पेनर ने यह कहा था कि विदेश में जो हमारा धन रखा है, अगर हम उसे वापस ले आएं तो हर हिन्दुस्तानी के खाते में 14-15 लाख रुपये आ जाएंगे। यह सब ऑन रिकॉर्ड है। यह सीडी में है। अब लोग इंतजार कर रहे हैं, चाहे 14 रुपये आए, चाहे 1400 रुपये आए या 14 लाख रुपये आए। अब सरकार कह रही है कि उतना रुपया नहीं है। यह आरोप लगाने की बात नहीं है। लेकिन यह भी एक भ्रष्टाचार है कि चुनाव में गलत कहना, गैर जिम्मेदारी से बात करना और उसका फायदा उठाने का मामला भी कम भ्रष्ट नहीं है। यह आचार हो सकता है, लेकिन यह सदाचार नहीं है, कदाचार हो सकता है। इसको मानना पड़ेगा। अब सरकार कह रही है और बेशक जो सत्वाई है, वह सामने आ रही है।

आज एक नेता के नाम से हम लोग क्या जानते हैं? हम सोचते हैं कि वह विजिनरी होगा, वह भविष्य को देखेगा कि 100 दिन बाद या 200 दिन बाद क्या होने वाला है? अगर सरकार को काले धन से निपटना है तो सिर्फ ये 627 नाम ही नहीं हैं बल्कि अभी मंत्री जी फिर कहेंगे कि हमने 627 नाम लिफाफे में लिखकर दे दिये हैं। लाखों भ्रष्ट हिन्दुस्तानियों ने करोड़ों अरबों रुपया विदेशों में जमा करके रखा है। सब भ्रष्ट नहीं हैं। लोग चाहते हैं कि उनका नाम उजागर हो। यूपीए की सरकार और एनडीए की सरकार भी कहती हैं कि उनके नाम नहीं लेंगे। चूंकि काले धन के जो मालिक हैं, उनके साथ सरकार का रिश्ता इतना नाजुक है कि वे लोगों के सामने आना पसंद नहीं करते। अभी जो 7-8 नाम आए हैं: 5 डायरेक्टर, 3 कंपनी, उसमें 3 लोगों का जो केस हुआ, उसमें देखा जाएगा कि बीजेपी ने जो 25000 करोड़ रुपया खर्च किया, उसमें इन तीन के अंदर दो का चंदा शामिल था। सदन में सरकार का जैसे बहुमत है, जनता के बीच में सरकार के 31 प्रतिशत वोट हों लेकिन काले धन के अंदर दो तिहाई बहुमत है। तीन में से दो का तो है ही। चुनाव में जो काले धन का इस्तेमाल होता है, उसको रद्द करना पड़ेगा। इसलिए इलैक्टोरल रिफॉर्मर्स चाहिए चाहे वह कांग्रेस पार्टी 15000 करोड़ रुपया खर्च करे चाहे भारतीय जनता पार्टी 25000 खर्च करे, कहां से चंदा आता है, वह मालूम होना चाहिए। वह पैसा आता है काले धन से, जैसा मैंने कहा। हमारी जो गाढ़ी

कमाई है, चाहे हमें मिनिमम वेजेज नहीं मिलती है, चाहे हमारा वर्किंग ऑवर से कम्प्लाइज होता है, चाहे हमारा सेफ्टी स्टैंडर्ड से कम्प्लाइज होता है, चाहे हमारे लैंड यूज के बारे में धपला किया जाता है, चाहे महिलाओं की ट्रेफिकिंग हो, चाहे हमारे बच्चों की ट्रेफिकिंग हो तथा चाहे वह ड्रग्स ट्रेफिकिंग हो, चाहे वह नार्कोटिक्स हो, वह पैसा विदेश में जाकर मॉरीशियस रूट से, पार्टिसिपेटरी नोट्स से, एफडीआई के नाम पर वापस आता है। आज सारा काला धन विदेश में नहीं रखा हुआ है। हम हर बार यहां पर बहस करते हैं। पिछली बार भी बहस की थी। उसके बाद सरकार मौका देती है। पिछली सरकार भी देती थी और यह सरकार भी दे रही है जिससे खाता तो रह जाए लेकिन वह खाता खाली हो जाए, उसमें रुपये नहीं रहे। यदि उस पैसे को लाने की सरकार में हिम्मत है तो यही सरकार जब सूपीए सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मॉरीशियस रूट के खिलाफ बोला था। डीटीए के बारे में भी यहां पर बोला गया था। ये तो टैक्स शॉरिंग है, ये तो जिस तरीके से लोग मॉल में जाते हैं, उसी तरीके से लोग यह देखना चाहते हैं कि कहां टैक्स हैवन है और वहां के रूट पकड़कर आते हैं। आज मॉरीशियस से जितने इन्वेस्टमेंट हुए, अगर सरकार पक्की है, पिछले दस साल का ही चाहे आप देख लें, सूपीए वन और सूपीए टू में मॉरीशियस के रूट

से कितने इन्वेस्टमेंट्स आए, उसका सोर्स क्या था? वह आप उजागर कर दो तब मालूम हो जाएगा कि किस तरह से काले धन को सादा करने की मशीन इस देश में चल रही है। उस मशीन को खत्म करना पड़ेगा वना हम काले धन से नहीं निपट पाएंगे। इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है। जो भ्रष्टाचार इस देश में हो रहा है और सरकारी शह में हो रहा है, उसको अगर हम खत्म नहीं कर सकते तो काले धन से हम नहीं निपट पाएंगे।